(v) एक उचित दर की दुकान के लिए कम से कम 4000 यूनिटों का आवंटन किया जाए।

(vi) उचित दर की दुकानों को बैंक ऋण देने की व्यवस्था की जाए।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर समय-समय पर इस बात के लिए जोर देती रही है कि उचित दर की दुकानों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। उनसे कहा गया है कि वे विनिर्माताओं से उन अन्य आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति स्वयं करें, जिन्हें वे उचित दर की दुकानों के तंत्र के माध्यम से उपभोक्ता में वितरित कर सकती हैं। इसी प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने तथा उचित दर की दुकानों में खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होने के के कारण, उन्हें दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वे हर 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दुकान खोलने के आधार पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाएं। इस संबंध में छितरी आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में जहां इस मांनदंड को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता है, छूट दी जा सकती है। राज्य सरकारें, प्राप्त हुई शिकायतों की जांच के आधार पर उचित दर की दुकानों के मालिकों के खिलाफ समय-समय पर कार्यवाही करती हैं। चूंकि आवश्यक वस्तुओं का कारोबार करने वाली उचित दर की दुकानें प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, अत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इस बात के लिए भी बल दिया गया है कि वे उचित दर की दुकानों के मालिकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों से पर्याप्त ऋण सुविधाएं दिलवाने के लिए प्रबंध करें।

सरकारी कालोनियों में सफाई

2450. **श्री रामचन्द्र विकल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाली सरकार कालोनियों ; सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है ;

(ख) क्या कुछ कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस कार्य को ठेकेदारों से ठेके पर कराता है, यदि हां, तो ऐसी कालोनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह कार्य कुछ पूछताछ में "हैंड रसीद" पर भर्ती कर्मचारियों से कराया जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार से 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की योजना को धक्का लगा है और इससे न केवल अनुसूचित जातियों के लोगों में बेरोजगारी ही बढ़ी है बल्कि सफाई व्यवस्था में भी गिरावट आई है ; और

(ङ) सरकार इस कार्य को ठेकेदारों से कराने की प्रथा को कब तक खत्म करने तथा इसे नियमित आधार पर भर्ती किए गए कर्मचारियों से कराने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

Inadequate pasture land near Ranthombore Park

2451. PROF. C. LAKSHMANNA:
SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of villages surrounding the Ranthombore Park area in Rajasthan have not adequate pastures lawn for their cattle numbering about 40,000; and

(b) if so, whether Government have taken any measures to provide adequate fodder to the villages for their cattle so that the Ranthombore National Park area is not damaged by the villagers?